



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261136
CG-DL-E-18022025-261136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 851]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946

No. 851]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी 2025

का.आ. 855 (अ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2733(अ), तारीख 22 अगस्त, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2733(अ), तारीख 22 अगस्त, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 2733(अ), तारीख 22 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के लिए, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“5. निगरानी समिति. – केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति के रूप में एक समिति होगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- | | | |
|--------|--|----------------------|
| (i) | क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | चामराजनगर जिले के हनूर निर्वाचन क्षेत्र, मांड्या जिले के मालवल्ली निर्वाचन क्षेत्र और रामनगर जिले के कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य* | - सदस्य, पदेन; |
| (iii) | पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (iv) | कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (v) | क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर | - सदस्य, पदेन; |
| (vi) | चामराजनगर, मांड्या और रामानगर जिलों के उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि। | - सदस्य, पदेन; |
| (vii) | प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या वन्य जीवन में एक विशेषज्ञ को हर तीन वर्ष के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किया जाएगा | - सदस्य; |
| (viii) | विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण या वन्य जीवन के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हर तीन वर्ष के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। | - सदस्य; |
| (ix) | सदस्य, कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड | - सदस्य, पदेन; |
| (x) | उप वन संरक्षक, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, कोल्लेगल | - सदस्य सचिव, पदेन।” |

6. निगरानी समिति के कृत्य.-(1) निगरानी समिति, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना स. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना और इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय होने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए यथास्थिति केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

- (3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
- (5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-VII** में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।”

[फा.सं. 25/160/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण.- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 22 अगस्त, 2017 को का.आ. 2733 (अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025

S.O. 855(E). — **WHEREAS** the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around the Cauvery Wildlife Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2733 (E), dated the 22nd August, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2733 (E), dated the 22nd August, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2733 (E), dated the 22nd August, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** — There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons, namely: -

- | | |
|---|--|
| (i) Regional Commissioner, Mysore | -Chairman, <i>ex officio</i> ; |
| (ii) Member of Legislative Assembly from Hanur Constituency of Chamarajanagar District, Malavalli Constituency of Mandya District and Kanakapura Constituency of Ramanagara District* | -Members, <i>ex officio</i> ; |
| (iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka | -Member, <i>ex officio</i> ; |
| (iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka | -Member, <i>ex officio</i> ; |
| (v) Regional officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore | -Member, <i>ex officio</i> ; |
| (vi) Deputy Commissioner or his representative of Chamarajanagar, Mandya and Ramanagar districts. | -Members, <i>ex officio</i> ; |
| (vii) One expert in ecology or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Karnataka after every three years | -Member; |
| (viii) One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka after every three years | -Member; |
| (ix) Member, Karnataka State Biodiversity Board | -Member, <i>ex officio</i> ; |
| (x) The Deputy Conservator of Forests, Cauvery Wildlife Sanctuary, Kollegal | -Member Secretary, <i>ex officio</i> . |

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).

6. **Functions of Monitoring Committee.** — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure VII.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/160/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2733 (E), dated the 22nd August, 2017.